Regd. No. CHD/0093/2015–2017

Haryana Government Gazette

Published by Authority

© Government of Haryana

No. 52-2017] CHANDIGARH, TUESDAY, DECEMBER 26, 2017 (PAUSA 4, 1939 SAKA)

CONTENTS

			Pages
PART I—	Notifications, Orders and Declarations by Haryana Government	. .	1873-1913
PART I-A—	Notifications by Local Government Department	. .	Nil
PART I-B—	Notifications by Commissioners and Deputy Commissioners	. .	Nil
PART II—	Statutory Notifications of Election Commission of India— Other Notifications and Republications from the Gazette of India	. .	Nil
PART III—	Notifications by High Court, Industries, Advertisements, Change of Name and Notices	. .	437-439
PART III-A—	Notifications by Universities	. .	Nil
PART III-B—	Notifications by Courts and Notices	. .	Nil
PART IV—	Act, Bills and Ordinances from the Gazette of India	. .	Nil
PART V—	Notifications by Haryana State Legislature	. .	Nil
SUPPLEMENT PART I—	Statistics–	. .	Nil
SUPPLEMENT PART II—	GENERAL REVIEW- Review of the Annual Administrative Report of Animal Husbandry and Dairying Department, Haryana for the year 2016-17	. .	161-163
LEGISLATIVE SUPPLEMENT —	Contents	. .	Nil
Ditto	PART I—Act	. .	Nil
Ditto	PART II—Ordinances	. .	Nil
Ditto	PART III—Delegated Legislation	. .	Nil
Ditto	PART IV—Correction Slips, Republications and Replacements	. .	Nil

Regd. No. CHD/0093/2015–2017

Haryana Government Gazette

Published by Authority

© Government of Haryana

No. 52-2017] CHANDIGARH, TUESDAY, DECEMBER 26, 2017 (PAUSA 4, 1939 SAKA)

PART-I

Notifications, Orders and Declarations by Haryana Government

हरियाणा सरकार

नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विभाग

आदेश

दिनांक 19 दिसम्बर, 2017

संख्या 22/52/2005–5P.— ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 (2001 का केन्द्रीय अधिनियम 52), की धारा 18 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, हरियाणा राज्य में ऊर्जा के सफल उपयोग तथा इसके संरक्षण हेतु निम्नलिखित निर्देश जारी करते हैं, अर्थातः–

नीचे अनुसूची के खाना 3 में वर्णित क्षमता के अनुसार खाना 2 में वर्णित भवनों/क्षेत्रों के प्रवर्ग के लिए सोलर फोटोवोलटाईक विद्युत संयंत्र की स्थापना आज्ञापक होगी, अर्थात,:-

अनुसूची

क्रम संख्या	भवन /क्षेत्र के प्रवर्ग	स्थापित किये जाने वाले सौर फोटोवोलटाईक विद्युत संयंत्र की क्षमता
1	2	3
1.	नगरनिगमों, नगर परिषदों, नगरपालिकाओं, हरियाणा नगरीय विकास प्राधिकरण तथा हरियाणा राज्य औद्योगिक अवसंरचना विकास निगम के सेक्टरों की सीमा के भीतर आने वाले 500 वर्ग गज तथा इससे अधिक आकार के भूखंड पर निर्मित सभी नये आवासीय भवन	कम से कम 1 किलोवाट अथवा सम्बद्ध भार का 5 प्रतिशत, जो भी अधिक हो

क्रम संख्या	भवन /क्षेत्र के प्रवर्ग	स्थापित किये जाने वाले सौर फोटोवोलटाईक विद्युत संयंत्र की क्षमता
1	2	3
2.	30 किलोवाट या अधिक सम्बद्ध भार वाले सभी नये निजी शैक्षणिक संस्थाओं, विद्यालयों, महाविद्यालयों, छात्रावासों, तकनीकी/व्यवसायिक शिक्षा संस्थानों, विश्वविद्यालयों इत्यादि	कम से कम 5 किलोवाट अथवा सम्बद्ध भार का 5 प्रतिशत, जो भी अधिक हो
3.	30 किलोवाट या अधिक सम्बद्ध भार वाले सभी सरकारी भवनों और कार्यालयों, सरकारी महाविद्यालयों, जिला शिक्षा तथा प्रशिक्षण संस्थान, सरकारी शैक्षणिक संस्थानों, विश्वविद्यालयों	कम से कम 2 किलोवाट अथवा सम्बद्ध भार का 5 प्रतिशत, जो भी अधिक हो
4.	ऐसे सभी नये निजी अस्पतालों तथा नर्सिंग होम, औद्योगिक प्रतिष्ठानों, व्यवसायिक प्रतिष्ठानों, मालों होटलों, मोटलों, समारोह हालों तथा पर्यटन काम्पलैक्सों जिनका सम्बद्ध भार (i) 50 किलोवाट से 1000 किलोवाट हो (ii) 1000 किलोवाट से अधिक हो	(i) कम से कम 10 किलोवाट अथवा सम्बद्ध भार का 5 प्रतिशत, जो भी अधिक हो (ii) कम से कम 50 किलोवाट अथवा सम्बद्ध भार का 3 प्रतिशत, जो भी अधिक हो
5.	समूह आवासीय समितियों, बिल्डरों, आवासन बोर्ड द्वारा निम्नलिखित आकार के भूखंड पर विकसित सभी नए आवासीय परिसर : (i) 0.5 एकड़ से 1 एकड़ (ii) एक एकड़ से अधिक और दो एकड़ तक (iii) दो एकड़ से अधिक और पांच एकड़ तक (iv) पांच एकड़ से अधिक	(i) कम से कम 10 किलोवाट (ii) कम से कम 20 किलोवाट (iii) कम से कम 30 किलोवाट (iv) कम से कम 40 किलोवाट
6.	100 किलोवाट और अधिक सम्बद्ध भार वाले सिंचाई विभाग के सभी वाटर लिफ्टिंग स्टेशन	कम से कम 50 किलोवाट अथवा सम्बद्ध भार का 3 प्रतिशत, जो भी अधिक हो

(i) ये आदेश पहले अधिसूचित आदेश संख्या 22/52/2005–5 पावर दिनांक 21/03/2016 का स्थान लेगें ।

(ii) नगर तथा ग्राम आयोजना, हुडा, भाहरी स्थानीय निकाय, हरियाणा राज्य औद्योगिक अवसंरचना विकास निगम, उद्योग व वाणिज्य, विभाग, सौर फोटोवोलटाईक विद्युत उत्पादन संयंत्रों की स्थापना के आज्ञापक प्रावधानों को क्रियान्वित करेंगे तथा सौर फोटोवोलटाईक विद्युत संयंत्रों का अनिवार्य उपयोग करने हेतु आदेश जारी होने की तिथि से तीन मास के भीतर अपने नियमों में इस संबंध में सुसंगत प्रावधान सम्मिलित करेगें। वे अपने विभाग के नियमों के अनुसार अधिसूचना को क्रियान्वित न करने पर दाण्डिक कार्यवाही, प्रक्रिया, दाण्डिक राशि निर्धारित करते हुए दिशा निर्देश जारी करेंगे।

(iii) लोक निर्माण विभाग (भवन तथा सड़कें), हरियाणा राज्य सड़क एवं सेतू विकास निगम, जन स्वास्थ्य, शिक्षा (सभी विभाग और मिशन परियोजनाएं), स्वास्थ्य (सभी विभाग और मिशन परियोजनाएं), सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, रैड क्रोस समितियां, वास्तुकला, आवासन बोर्ड, हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड, सिंचाई, वन,

पुलिस आवास निगम, पर्यटन, राज्य विश्वविधालय या सरकार का भवन निर्माण करने वाला अन्य विभाग अपने द्वारा निर्मित सभी भवनों में आज्ञापक प्रावधानों की अनुपालना के तहत सौर फोटोवोलटाईक विद्युत उत्पादन संयंत्रों की स्थापित करेंगे।

(iv) अक्षय ऊर्जा विभाग, ऊर्जा सरंक्षण अधिनियम क्रियान्वित करने के लिए राज्य नामित अभिकरण के रूप में सरकारी विभागों/संगठनों को सौर विद्युत संयंत्र स्थापित करने में परियोजना प्रस्ताव, मूल्य अनुमान तैयार करने में, तथा नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार से समय–समय पर प्राप्त होने वाले केन्द्रीय वित्तीय सहायता (यदि उपलब्ध हो) को प्राप्त करने के लिए आवश्यक तकनीकी सहयोग प्रदान करेगा ।

(v) सम्बंधित विभाग राज्य सरकार के उक्त निर्णय को लागू करने की निगरानी तथा प्रगति रिपोर्ट अक्षय ऊर्जा विभाग, हरियाणा को त्रैमासिक आधार पर अक्षय ऊर्जा विभाग द्वारा जारी किये जाने वाले प्रपत्रों में संबंधित अपर उपायुक्त –एवं –मुख्य परियोजना अधिकारी के माध्यम से भेजने के लिए जिला तथा राज्य स्तर पर नोडल अधिकारी पदाभिहित करेगे । इन रिपोर्ट के आधार पर अक्षय ऊर्जा विभाग, हरियाणा गुणवत्ता/तकनीकी आंकलन करेगा। यदि संतोषजनक नहीं पाया जाता तो संबंधित विभाग नियमानुसार उक्त दाण्डिक कार्यवाही करेगा ।

(vi) उपरोक्त संगठन /उपयोगकर्ता प्रवर्ग संबंधित विभाग द्वारा जारी दिशा निर्देश (उपरोक्त पैरा (iii) के अनुसार) के 6 महीनें के भीतर अपने मूल्य पर उपरोक्त वर्णित आज्ञापक प्रावधानों की अनुपालना सुनिश्चित करेंगे, जिसमें असफल होने पर जिस संबंधित विभाग द्वारा दाण्डिक कार्यवाही की जायेगी।

टिप्पणी: इन आदेशों की अवहेलना की स्थिति में, विद्युत उपयोगिता विभाग को उपरोक्त वर्णित अन्तिम तिथि के समाप्त होने के उपरान्त उचित नोटिस देने के बाद बिजली के कनैक्शन काटने का अधिकार होगा। विद्युत उपयोगिता विभाग के कार्यकारी अभियन्ता (प्रचालन) इन आदेशों को लागू करने के प्राधिकारी होंगे तथा व इस बारे में अपने जिले के अतिरिक्त उपायुक्त को त्रैमासिक रिपोर्ट भेजेंगे जो क्रमशः एक संकलित त्रैमासिक रिपोर्ट अक्षय ऊर्जा विभाग, हरियाणा (ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 (2001 का 52) के अधीन राज्य अभिहित अधिकरण) को प्रस्तुत करेगा।

(vii) स्थापित संयंत्र नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार / अक्षय ऊर्जा विभाग, हरियाणा/हरियाणा अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण (हरेडा) द्वारा विहित तकनीकी विनिदेशा को सख्ती से अनुपालना करेंगे। तकनीकी विनिदेशा अक्षय ऊर्जा विभाग की वेबसाईट www.hareda.gov.in से ली जा सकती है ।

(viii) निजी सेक्टर के उपयोगकर्ता प्रवर्ग या तो नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार या अक्षय ऊर्जा विभाग, हरियाणा/हरियाणा अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण द्वारा पैनल में शामिल चैनल पार्टनर्स/नये उपकरण/फर्म के माध्यम से सौर फोटोवोलटाइक ऊर्जा संयंत्र स्थापित कर सकते है। जबकि सरकारी विभाग/संगठनों के लिए अक्षय ऊर्जा विभाग, हरियाणा को राज्य नामित अभिकरण अनुमोदित स्त्रोत है। पैनल में शामिल चैनल पार्टनर्स/नये उपकरण/फर्म की सूची अक्षय ऊर्जा विभाग की वेबसाईट www.hareda.gov.in से ली जा सकती है।

(ix) निदेशक, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विभाग द्वारा स्थापित होने वाली अधिकतम श्रमता तक कम की जा सकती है। जिसके लिए समबन्धित जिले के परियोजना अधिकारी द्वारा यह प्रमाणित किया जाना होगा की विशेष भवन पर अधिकतम विशेष किलोवाट का सोलर पावर पलाट लग सकता है। व भवन पर इससे अधिक छाया मुक्त स्थान उपलब्ध नहीं है।

(x) निजी क्षेत्र में नयी इमारतों के लिए यह अधिसूचना, हरियाणा बिल्डिंग कोड 2016 के जारी होने की तारीख, 30–06–2016, से लागु हागी तथा अन्य के लिए यह अधिसूचना प्रकाशन तिथी से लागु होगी।

टिप्पणी: यदि उपरोक्त आदेश के तहत किसी प्रवर्ग के एक से अधिक परिषद/यूनिट है तो वह किसी एक या अधिक परिषद में अधिसूचना के अन्तर्गत अपनी जरूरत को पूरा करने के लिए कुल क्षमता का सौर ऊर्जा संयंत्र लगवा सकता है।

अंकुर गुप्ता,
प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,
नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विभाग, चण्डीगढ।

HARYANA GOVERNMENT

NEW & RENEWABLE ENERGY DEPARTMENT

Order

The 19th December, 2017

No. 22/52/2005-5P.— In exercise of the powers conferred by section 18 of the Energy Conservation Act, 2001(Central Act 52 of 2001), the Governor of Haryana hereby issues the following directions for efficient use of energy and its conservation in the State of Haryana.

The installation of Solar Photovoltaic Power Plant for the category of buildings/areas mentioned in column 2 as per the capacity mentioned against it under column 3 of the schedule below shall be mandatory.

SCHEDULE

Sr. No.	Category of building/area	Capacity of Solar Photovoltaic Power plant to be installed
1	2	3
1	All new residential buildings built on a plot size of 500 Square Yards and above falling within the limits of Municipal Corporations, Municipal Councils, Municipal Committees, Haryana Urban Development Authority (HUDA),Haryana State Industrial and Infrastructure Development Corporation (HSIIDC) sectors	Minimum 1 Kilo Watt peak (KWp) Or 5% of sanctioned load, whichever is higher
2	All new private Educational Institutes, Schools, Colleges, Hostels, Technical/Vocational Education Institutes, Universities etc. having sanctioned load of 30 Kilo Watt (KW) and above	Minimum 5 Kilo Watt peak (KWp) Or 5% of sanctioned load, whichever is higher
3	All Government Buildings and Offices, Government Colleges, District Institute of Education and Training (DIET), Government Educational Institutions, Universities, having sanctioned load of 30 Kilo Watt (KW) and above	Minimum 2 Kilo Watt peak (KWp) Or 5% of sanctioned load, whichever is higher
4	All new private Hospitals and Nursing Homes, Industrial Establishments, Commercial Establishments, Malls, Hotels, Motels, Banquet Halls and Tourism Complexes, having sanctioned load (i) of 50 Kilo Watt (KW) to 1000 Kilo Watt (KW); (ii) above 1000 Kilo Watt (KW)	(i) Minimum 10 Kilo Watt peak (KWp) or 5% of sanctioned load, whichever is higher; (ii) Minimum 50 Kilo Watt peak (KWp) or 3% of sanctioned load, whichever is higher
5	All new Housing Complexes, developed by Group Housing Societies, Builders, Housing Boards, on a plot size of: (i) 0.5 Acre to 1.0 Acre; (ii) More than 1.0 Acre to 2.0 Acres; (iii) More than 2.0 Acres to 5.0 Acres; (iv) More than 5.0 Acres.	(i) Minimum 10 Kilo Watt peak (KWp) (ii) Minimum 20 Kilo Watt peak (KWp) (iii) Minimum 30 Kilo Watt peak (KWp) (iv) Minimum 40 Kilo Watt peak (KWp)
6	All water lifting stations of Irrigation Department having sanctioned load of 100 Kilo Watt (KW) and above	Minimum 50 Kilo Watt peak (KWp) Or 3% of sanctioned load, whichever is higher

(i) This order supersede the order notified vide No. 22/52/2005-5 Power dated 21st March, 2016.

(ii) The Departments of Town and Country Planning, HUDA, Urban Local Bodies, Haryana State Industrial and Infrastructure Development Corporation (HSIIDC), Industries and Commerce (*i.e.* the concerned authority) shall issue the Occupation Certificate only after complying with the provisions of this notification.

(iii) Departments of Public Works (Buildings and Roads), Haryana State Roads & Bridges Development Corporation, Public Health, Education (all departments and Mission mode projects), Health (all departments and Mission mode projects), Social Justice and Empowerment, Red Cross Societies, Architecture, Housing Board, Haryana State Agricultural Marketing Board (HSAMB), Irrigation, Forest, Police Housing Corporation, Tourism, State Universities or any other government building constructed shall implement the mandatory provisions of installation of Solar Photovoltaic Power Generation Plant for the buildings constructed by them.

(iv) The Renewable Energy Department being a State Designated Agency for implementing Energy Conservation Act in the State shall provide all necessary technical support to the Government Departments/Organizations in preparation of project proposal, cost estimates, installation of Solar Power Plants and in obtaining the Central Financial Assistance(CFA) from Ministry of New and Renewable Energy (MNRE), Government of India (GOI), if available, from the Ministry of New and Renewable Energy, Government of India, from time to time.

(v) The concerned departments shall designate a District and State level Nodal Officer to monitor and to report the progress of enforcement of the said decision of the State Government, to the Renewable Energy Department, Haryana, on quarterly basis in the formats to be issued by Renewable Energy Department through the office of respective Additional Deputy Commissioner-cum-Chief Project Officer. Based on these reports the Renewable Energy Department will do quality/technical checks. If found not satisfactory then concerned department will take appropriate penal action as mentioned above.

(vi) The above said organizations/user categories shall ensure the compliance of above mentioned mandatory provisions, within six months from the date of issue of concerned department's new guidelines/notification (as per clause (iii) above), at their own cost, failing which, the penal action may be initiated by the respective departments.

*(**Note:** In case of non-compliance of these orders, the Power Utilities Department shall have the power to disconnect the electricity connections after serving due notice on expiry of the deadline mentioned above. The Executive Engineer (Operation) of the Power Utilities Department shall be the enforcing authority of these orders and they shall send quarterly progress reports in this regard to the Additional Deputy Commissioner of their district who in turn shall submit a compiled quarterly report to the Renewable Energy Department, Haryana (the State Designated Agency under the Energy Conservation Act, 2001(Central Act 52 of 2001))." However, if the Power Utilities Department fails to comply with the directions of the government, then the responsibility shall also be fixed for non-compliance of the directions.)*

(vii) The systems installed shall strictly comply with the technical specifications prescribed by Ministry of New and Renewable Energy, Government of India/ Renewable Energy Department, Haryana/ Haryana Renewable Energy Development Agency (HAREDA). The technical specifications may be downloaded from the website of the Renewable Energy Department www.hareda.gov.in.

(viii) The user categories of private sector may install the Solar Photovoltaic Power Plants either from the Channel Partners/New Entrepreneurs/ firms empanelled by Ministry of New and Renewable Energy or from the firms empanelled by Renewable Energy Department, Haryana/ Haryana Renewable Energy Development Agency (HAREDA) and for government departments/organizations, Renewable Energy Department, Haryana is the approved source, being State Designated Agency. The list of Channel Partners/New Entrepreneurs/ firms empanelled by MNRE/HAREDA may be downloaded the website of the Renewable Energy Department www.hareda.gov.in.

(ix) For the buildings where the installation of SPV systems have been mandated and sufficient shadow free area is not available due to one reason or the other, the mandated capacity shall be reduced upto the maximum capacity which may be installed on the building by Director, New & Renewable Energy Department.. For this Project Officer of the concerned district shall certify that on the particular building the solar power plant of maximum capacity in kWp may be installed and there is no shadow free space available on the building for installation of solar power plant of more than this capacity.

(x) For new buildings in private sector, the notification may be applicable for the building for which the building plan is sanctioned after 30.06.2016, the date of issue of The Haryana Building Code 2016, and for other it may be applicable from the date of its publication.

Note: if any of the category mentioned in the mandate above have more than one complex/unit, then to fulfill their obligation under this notification, they may install the system in one or more complex, within the State, combining the total requirement as per notification.

ANKUR GUPTA,
Principal Secretary to Government Haryana,
New & Renewable Energy Department.

55836—C.S.—H.G.P., Chd.